



भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कामयाब

450 किमी ऊपर कक्षा में पहुंचा; पीएम मोदी ने फोन पर बात कर बधाई दी

सबऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 चद्र की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम-1 450 चद्र की पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। इस सक्सेसफुल लॉन्च को भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सोने के कलाम, साराभाई और सीवी रमन भी भेजे गए

इस लॉन्चिंग को 'मिशन आगमन' नाम दिया गया था। इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में भेजे गए

कॉमर्शियल और टेक्नोलॉजी पेलोड्स:

- ग्रह स्पेस का टेक्नोलॉजी पेलोड।
- कॉस्मोसर्व स्पेस का पेलोड।
- डीक्यूबड का स्पेस रिसर्च से जुड़ा पेलोड।
- खुद स्कार्ईस्ट एयरोस्पेस का अपना इन-हाउस स्कोप पेलोड।

18 कैरेट सोने से बना आर्ट पीस भी स्पेस में भेजा गया :

कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति 'कॉस्मिक ब्लूम' और एक खास माइक्रो-आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। यह माइक्रो-आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सर सी वी रमन, डॉ. विक्रम साराभाई और डॉ. कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी रॉकेट में भेजा गया, जिस पर 'वंदे मातरम्' शब्द अंकित हैं।

: द्नीफ बॉक्स :

आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार से मांगी मेडिकल रिपोर्ट



जोधपुर,एजेंसी। जोधपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आसाराम ने अदालत से कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर यह बताए कि क्या उनकी स्वास्थ्य स्थिति वास्तव में इतनी गंभीर है कि उन्हें इलाज के लिए कुछ समय की अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सरकार ने क्या दिया जवाब?

हालांकि, राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फिलहाल आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है। उन्होंने कहा कि करीब तीन महीने पहले आसाराम अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे, जहां उन्होंने पैदल घूमकर दर्शन किए थे। इसके बावजूद सरकार संबंधित अधिकारियों से ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट और अन्य आवश्यक जानकारी लेकर अदालत के सामने पेश करेगी।

योगी बोले: ललिता गौतम हत्याकांड के दोषी बरेंगे नहीं

परिवार से मुलाकात की, 5 लाख की मदद, आवास देंगे; गाजियाबाद में अपनी बहन के घर भी गए



गाजियाबाद,एजेंसी। सीएम योगी ने शनिवार को गाजियाबाद में ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की। योगी ने PWD गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक ललिता के परिवार से बात की। कहा- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगी।

उन्होंने परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद, पिता और चाचा को एक-एक मुख्यमंत्री आवास देने का ऐलान किया। पुलिस अफसरों से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली।इससे पहले, पूर्व आईपीएस और मंत्री असीम अरुण सुबह साढ़े 9 बजे ललिता गौतम के परिवार को मेरठ से लेकर गाजियाबाद पहुंचे। मेरठ में बीए की दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या हुई थी। शव 17 मई को गन्ने के खेत में मिला था।

पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया था। SSP अविनाश पांडेय ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को थपड़ डारें। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद मामला ने तूल पकड़ लिया था।

वांगचुक को अनशन के 21वें दिन पुलिस ने अस्पताल भेजा

● पुलिस शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई

● जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं दीपके



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सुबह करीब 7 बजे पुलिस सिविल ड्रेस में जंतर-मंतर पहुंची थी और वांगचुक को सफेद चादर में उठाकर एंजुलेंस से अस्पताल भेजा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया, जिससे वहां हंगामा हो गया।वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। उनका वजन करीब 9.5 किलो कम हो गया है।हादरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक को रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज कराया जाए।

अरुणाचल प्रदेश के 35 गांवों में लैंडस्लाइड

यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; राजस्थान में इस साल 21% कम बारिश हुई



नई दिल्ली, एजेंसी। यूपी के लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी समेत सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी है। झांसी में 15 मिनट की बारिश के बाद पारा 7 डिग्री तक कम हो गया। राजस्थान में मानसून अब भी बेक पर है। राज्य में अब तक सामान्य से 21 फीसदी कम बरसत हुई है। वहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर समेत 44 जिलों में शनिवार को बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव लो प्रेशर एरिया और राजस्थान में एक्टिव सायक्लोनिक सर्क्युलेशन के चलते आने वाले दिनों में बारिश और बढ़ सकती है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में अपर सुबनसिरी जिले के गिबा, निलिंग, चेतम और दाभारिजो सर्किलों के 35 गांवों में प्लेश फ्लड और लैंडस्लाइड हुई।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का चौथा दल धारचूला में फंसा

अब कोई भी प्राइवेट कंपनी खोल सकेगी मेडिकल कॉलेज

भूस्खलन से 18 सड़कें बंद; केदारनाथ मार्ग पर भी पत्थर गिरे, पैदल यात्रा जारी



अधिकारियों ने यात्रियों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया। पहले दल में 49 में से 48 यात्री कैलाश मानसरोवर पहुंचे थे। इनके साथ एक डॉक्टर और तीन किचन स्टाफ भी शामिल थे। लौटने के बाद दल गुंजी होते हुए बुंदी के लिए रवाना हुआ।उधर, तीसरे दल ने शनिवार सुबह लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश किया, जबकि दूसरा दल फिलहाल कैलाश परिक्रमा पर है। वहीं चौथा दल सड़क की स्थिति सामान्य होने के बाद धारचूला से गुंजी के लिए रवाना किया जाएगा।

अधिकारियों ने यात्रियों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया। पहले दल में 49 में से 48 यात्री कैलाश मानसरोवर पहुंचे थे। इनके साथ एक डॉक्टर और तीन किचन स्टाफ भी शामिल थे। लौटने के बाद दल गुंजी होते हुए बुंदी के लिए रवाना हुआ।उधर, तीसरे दल ने शनिवार सुबह लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश किया, जबकि दूसरा दल फिलहाल कैलाश परिक्रमा पर है। वहीं चौथा दल सड़क की स्थिति सामान्य होने के बाद धारचूला से गुंजी के लिए रवाना किया जाएगा।

होर्मुज स्ट्रेट में दो तेल टैंकरों में विस्फोट

► यूएस का लगातार सातवीं रात ईरान पर हमला

► ईरान बोला-जमीनी हमले हुए तो कुवैत-बहरीन में घुस जाएंगे



केरम द्वीप और यज्द को निशाना बनाया गया।उधर, ईरानी सांसद अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा।

अमेरिकी हमले के बाद ईरान के 20 गांवों में पानी संकट

ईरान की अर्ध-सरकारी तस्वीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान के जस्क काउंटी के बुंजी तटीय गांव में समुद्री पानी को मीठ बनाने वाले सिस्टम पर अमेरिकी हमले के बाद 20 गांवों के करीब 10 हजार लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं।होमोंजगान वाटर और वेस्टवाटर कंपनी चपेट में आ गए।हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इस दावे को झूठ बताया। वहीं, CENTCOM ने कहा कि उसने लगातार सातवीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक, इन हमलों में सीरिक, बुशेहर, बंदर अब्बास,

केरम द्वीप और यज्द को निशाना बनाया गया।उधर, ईरानी सांसद अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा।

अमेरिकी हमले के बाद ईरान के 20 गांवों में पानी संकट

ईरान की अर्ध-सरकारी तस्वीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान के जस्क काउंटी के बुंजी तटीय गांव में समुद्री पानी को मीठ बनाने वाले सिस्टम पर अमेरिकी हमले के बाद 20 गांवों के करीब 10 हजार लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं।होमोंजगान वाटर और वेस्टवाटर कंपनी चपेट में आ गए।हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इस दावे को झूठ बताया। वहीं, CENTCOM ने कहा कि उसने लगातार सातवीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक, इन हमलों में सीरिक, बुशेहर, बंदर अब्बास,

पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 की मौत

15 से ज्यादा घायल



नजदीक के लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल आरएफ कैप के पीछे वस्त्राल के नजदीक बताया जा रहा है। फायर कर्मचारी आग पर काबू पा चुके हैं।

अहमदाबाद,एजेंसी। अहमदाबाद के महमूदपुरा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 से अधिक लोग जखमी हुए हैं। महापौर और मनपा आयुक्त घटनास्थल पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आज दोपहर शहर के वस्त्रा क्षेत्र में रामोल-गतराद रोड पर स्थित महमूदपुरा टैलेंट फायरवर्क्स फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पटाखों का कारखाना होने के कारण आग ने तेजी से भयंकर रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया।

आग लगने से 8 लोगों की मौत:महमूदपुरा में मेहुल डेडिया नामक एक व्यक्ति ने पटाखा फैक्ट्री चला रखी थी शनिवार दोपहर उसमें अचानक आग लगी जोरदार धमाका हुआ इसमें आठ लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि 15 से अधिक को

नजदीक के लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल आरएफ कैप के पीछे वस्त्राल के नजदीक बताया जा रहा है। फायर कर्मचारी आग पर काबू पा चुके हैं।

डोपड़ी जैसी जगह पर चल रही थी फैक्ट्री- महापौर

अहमदाबाद के महापौर हितेश बारोट एवं मनपा के आयुक्त बख्श निधि पानी भी मौके पर पहुंचे हैं। महापौर ने बताया कि घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, यह फैक्ट्री डोपड़ी जैसी जगह पर चल रही थी इसके कारण आग लगी बताई। आग की भयावहता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।महापौर ने बताया कि घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, यह फैक्ट्री डोपड़ी जैसी जगह पर चल रही थी इसके कारण आग लगी बताई।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किया नियमों में बदलाव



नई दिल्ली, एजेंसी। मेडिकल कॉलेज खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने अपने नियम में बदलाव किया है। पहले सिर्फ सेक्शन-8 वाली नॉन-प्रांफिट कंपनियों को ही मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाजत थी। अब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी किसी भी कंपनी को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी।

सेक्शन-8 कंपनी नॉट-प्रांफिट होती है। इसमें कमाई का बचा हुआ पैसा सिर्फ चैरिटी या संस्थान के विकास में ही लगाया जा सकता है, मुनाफे के तौर पर नहीं निकाला जा सकता।

2017 में तत्कालीन मेडिकल कार्जिसल ऑफ इंडिया ने कहा था कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड सभी कंपनियां मेडिकल कॉलेज खोल सकती हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी भी कंपनी में बद सकते थे। 2019 में MCI के भंग होने के बाद NMC बनी। उसने फिर से नियम सख्त कर दिए और सिर्फ सेक्शन-8 कंपनियों को ही इजाजत दी।

भारतीय नौसेना को मिला एक और एमएच-60आर सीहॉक हेलिकॉप्टर, जल्द दो और चॉपर मिलेंगे



नई दिल्ली,एजेंसी। अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय नौसेना को एक और एमएच-60आर सीहॉक हेलिकॉप्टर मिल गया है। यह हेलिकॉप्टर पिछले सप्ताह कोच्चि पहुंचा। दूतावास ने कहा कि इस सप्ताह दो और हेलिकॉप्टर भारत पहुंचने वाले हैं, जो भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के लगातार मजबूत होने का संकेत है।अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक नौसैनिक हेलिकॉप्टर भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी और अन्य अभियानों की क्षमता को और मजबूत करेगा। भारत ने फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ 24 एमएच-60आर सीहॉक हेलिकॉप्टर खरीदने का समझौता किया था।

यह ब्लैकहॉक हेलिकॉप्टर का समुद्री संस्करण है, जिसे हर मौसम में काम करने के लिए तैयार किया गया है।



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



सब नागरिक समान सबको सम्मान

समानता और न्याय की
भावना को समर्पित

मध्यप्रदेश

मंत्रिपरिषद् बैठक

अध्यक्षता

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

19 जुलाई 2026

जगदीशपुर, जिला भोपाल



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश की जनहितैषी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

समान नागरिक संहिता



सभी जाति, धर्म या वर्ग के नागरिकों
के लिए एक समान कानून
सुनिश्चित होंगे



सभी पारंपरिक सांस्कृतिक विविधताएं,
धार्मिक रीति-रिवाज पूरी
तरह सुरक्षित होंगे



विवाह, तलाक, भरणपोषण, उत्तराधिकार
जैसे मामलों में अब सभी को एक समान
कानूनी सुरक्षा मिलेगी



जुबानी, एकतरफा और अनौपचारिक
तलाक पूरी तरह गैर-कानूनी
और दंडनीय होंगे



बहुविवाह पर पूरी तरह रोक एवं विवाह
और तलाक पर पंजीयन
अनिवार्य होगा



लिव-इन रिलेशनशिप का
पंजीयन अनिवार्य



माता-पिता की वैवाहिक स्थिति से परे सामान्य
बच्चों की तरह जैविक, दत्तक, सेरोगेसी या
एआरटी से जन्मे बच्चों को समान
कानूनी मान्यता



जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान
करते हुए प्रदेश की भील, गोंड, कोरकू, बैगा,
सहरिया और भारिया जैसी जनजातियों पर
यह कानून लागू नहीं होगा

वनांचल कुसमी में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत
जानने पहुंचे कलेक्टर, मरीजों से लिया फीडबैक



मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र.) जिले के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र कुसुमी में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत एवं जनकेंद्रित बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसुमी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनांचल क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समय पर बेहतर उपचार, आवश्यक दवाएं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कलेक्टर ने कहा कि कुसुमी जैसे भीगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ऐसे में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

निरिक्षण के दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का भ्रमण किया उन्होंने औपीडि, वार्ड, प्रसूति कक्ष, औपधि भंडार, प्रयोगशाला सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों, मरीजों की दवा रही सेवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद किया उन्होंने मरीजों से उपचार की गुणवत्ता, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के व्यवहार, दवाओं की उपलब्धता और जांच सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की उन्होंने मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को आवश्यक सुधारालोक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए किसी भी मरीज को उपचार के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए उन्होंने स्वास्थ्य अमल को निर्देशित किया कि मरीजों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव मिले कलेक्टर ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता, आवश्यक जांच सुविधाओं और नियमित स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई, अनुशासन और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक



प्राभावी रूप से यहनुँचाया जाए अवस्यक है समय पर उपस्थित विशेष रूप से वानांचल क्षेत्रों में रहकर मरीजों को उपचार देने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य नियमित प्रयास किए जाए सेवाओं की निगरानी करना उन्हींके हाथ कि जिले का कोई और लोगों में स्वास्थ्य नहिं नागरिक केवल दूरी या जागरूकता बढ़ाना प्रार्थमिकता भौगोलिक कठिनाइयों के कारण में शामिल बहाना चाहिए। उपचार से वंचित नहीं रहना निरीक्षण के दौरान मुख्य चाहिए कलेक्टर एवं स्वास्थ्य नचिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार अधिकारियों और स्वास्थ्य खरे, मुख्य कांपालन अधिकारी जनपद पंचायत कर्मचारियों को निर्देश देने हुए ज्ञानंद मिश्रा, तदसलंदार कइका ग्रामीण एवं वानांचल नारायण सिंह सहित स्वास्थ्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को विभाग के अधिकारी और मजबूत बनाने के लिए टीम कर्मचारी उपस्थित रहे। भावना के साथ कार्य करना

आवश्यक है समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को उपचार उपलब्ध करना, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना और लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ज्ञानेंद्र मिश्रा, तहसीलदार नारायण सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।



**मैहर जिला किसान कांग्रेस की कार्यकारिणी
घोषित, नए पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी**

मीडिया ऑडिटर, मेहर (निप्र)। मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस को मेहर जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज सिंह बबेल द्वारा नई कार्यकारिणी जारी करते हुए ब्लॉक अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को नियुक्ति की गई है नई नियुक्तियां प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की सहमति और अनुमोदन के बाद प्रभावी की गई हैं।

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश किसान कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान के अनुमोदन एवं निर्देश के बाद मेहर जिला किसान कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित की गई इस प्रक्रिया में मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह (राहुल भैया), अमरगढन विधायक एवं पूर्व विधानसभा उपअध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह तथा मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभाग एवं प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह चौहान की सहमति भी शामिल रही। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज सिंह बबेल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की जिम्मेदारियां सौंपी हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी की रीति-नीति और सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य-



करते हुए किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और उनकी आवाज को मजबूती प्रदान करेंगे। घोषित कार्यकारिणी में जिले के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्षों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है संगठन ने कहा कि नई टीम किसानों से सीधे संबंध स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करेंगे। किसान कांग्रेस ने बताया कि नई कार्यकारिणी आज से प्रभावी मानी जाएगी। संगठन का उद्देश्य जिले में किसान हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना, किसानों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करना और कांग्रेस के संगठनात्मक ढाँचे को और मजबूत करना है नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर किसानों के बीच संगठन को मजबूत करेंगे और किसान हितों के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

करते हुए किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएँ और उनकी आवाज को मजबूती प्रदान करें। घोषित कार्यक्रमों में जिले के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्षों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है संगठन ने कहा कि नई दुई किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान को लिए लागतार प्रयास करेंगे किसान कौल से बताया कि नई कार्यक्रमों आज से प्रभावी मानी जाएँगी संगठन का उद्देश्य जिले में किसानों हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना, किसानों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना और कौल से सोटानाकम ढँच को और मजबूत करना है नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर किसानों के बीच संगठन को मजबूत करें और किसान हितों के लिए निरंतर कार्य करें।

**दुग्ध समृद्धि अभियान से गांव बनेंगे आत्मनिर्भर,
आधुनिक पशुपालन से किसानों की आय बढ़ेगी: सांसद**



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को सीधी जिले की ग्राम पंचायत रामपुर एवं पड़री में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा शामिल हुए इस दौरान उन्होंने किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों से संवाद कर वैज्ञानिक पशुपालन गौ संरक्षण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत रामपुर में गौ पूजन के साथ हुआ सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौशायक विशेष महत्व है और गौ आधारित कृषि एवं पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का

प्राचीन मान्यता है उन्होंने जैविक खेती, गोबर से बायोगैस निर्माण, गौ आधरित उत्पादों के उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इन उपायों को अपनाकर गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए दुध उत्पादन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग समय की आवश्यकता है केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को मान्यता दे पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों का लाभ दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है सांसद डॉ. मिश्रा ने ग्राम पट्टी में पशुपालक छोटेलाल जायसवाल के निवास पहुंचकर उनके पशुधन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि वहां मौजूद बछड़े कुम्रि गर्भाधान (आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन) तकनीक से प्राप्त हुए हैं सांसद ने इसे आधुनिक पशुपालन का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि इस तकनीक से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार, दुध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आय बढ़ने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है उन्होंने अधिक से अधिक किसानों और पशुपालकों से इस तकनीक का अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुध समृद्धि संपर्क अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का एक ज्वनआंदोलन है ।



मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)
जले में गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुख शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा ने शनिवार को कुसमी विद्यासखंड का व्यापक भ्रमण किया इस दौरान उन्होंने विद्यालयों, छात्रवासों और निर्माणाधीन शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों एवं शिक्षकों को सावधान्यक अधिकारों कुसमी दिए कलेक्टर ने आदर्श विद्यालय निर्देश में प्राचार्यों और छात्रवास

अधीक्षकों की बैठक लेकर शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर, छात्रावास संचालन और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसके लिए विद्यालयों में नियमित और प्रभावी शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा विद्यार्थियों की प्रगति का लगातार मूल्यांकन किया जाए बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल गतिविधियों और विद्यालयों में उपलब्ध अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए उन्होंने शिक्षकों से कहा कि विद्यार्थियों में अनुशासन, नैतिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और प्रतियोगी सोच विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। छात्रावास व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधीक्षकों को निर्देश दिए कि छात्रावासों में स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक भोजन, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य परीक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं उन्होंने कहा कि छात्रावास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। कलेक्टर ने युवाओं को भारतीय सेना में अधिक अवसर उपलब्ध कराते उद्देश्य से संचालित 'उजियार' कार्यक्रम के प्रभावी संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर पात्र विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें अनिवार्य भर्ती के तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण, शारीरिक अभ्यास, कैसरिय मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की जाए ताकि जिले के अधिक से अधिक युवा सफलता प्राप्त कर सकें निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सांदीपनि विद्यालय कुर्मी, कुरुकु च्छल भूमाइड और हाईस्कूल केशलार का भ्रमण किया उन्होंने शिक्षकों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम खेल गतिविधियों और परिसर की स्वच्छता का निरीक्षण किया विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएँ—उन्होंने कहा कि छात्रावास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। कलेक्टर ने युवाओं को भारतीय सेना में अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित 'उजियार' कार्यक्रम के प्रभावी संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर पात्र विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण, शारीरिक अभ्यास, कैरिक्युलम मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की जाए ताकि जिले के अधिक से अधिक युवा सफलता प्राप्त कर सकें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सांदिपनि विद्यालय कुसुमि, कुरुकु स्कूल भूमाइड और हाईस्कूल केशलार का भ्रमण किया उन्होंने कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम खेल गतिविधियों और परिसर की स्वच्छता निरीक्षण किया विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

सगरा पुलिस ने चलाया नशामुक्ति जागरूकता अभियान, विद्यार्थियों को दिलाई नशे से दूरी की शपथ



मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' जागरूकता अभियान के तहत सगरा पुलिस ने सीएम गड़ज स्कूल सगरा में विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशे से दूर रहने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। जागरूकता कार्यक्रम में उपनिरीक्षक दीपक तिवारी

न विद्यार्थियों को संवेधित करते हुए कहा कि नशा एक ऐसा समाजिककलहकर्म है जो धीरे-धीरे व्यक्ति के सुस्थ-साथ-उत्तम-पक्ष और पुरे समाज को प्रभावित करती है उन्होंने कहा कि नशे की आदत व्यक्ति के स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं में बढ़ता नशे का चलन एक गंभीर जिंता कि वियल है कई नए इसी शुरुआत कर रहे हैं शौक, दोस्तों के दबाव या मानसिक तनाव के कारण होती है लेकिन धीरे-धीरे यही सब आदत बनने लत में बदल जाती है। इससे प्रचुर के लिए जागृकता और मजबूत इच्छाशक्ति सबसे बड़ा माध्यम है उपनियंत्रण कर्तव्य न विद्यार्थियों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के तनाव

या पेशेजानी की स्थिति में नशे का सहारा लेने के बजाय परिवार के सदस्यों, मित्रों या विशेषज्ञों से बातचीत करनी चाहिए—उन्होंने कहा कि समय पर सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलने से व्यक्ति नशे की आदत से बच सकता है। उन्होंने परिवारभावकों को भी अपनी की की वे अपने बच्चों के व्यवहार और गतिविधियों पर ध्यान रखें तथा उनके साथ दोस्ताना संबंध बनाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें परिवार का सहयोग युवाओं को गलत रास्ते से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्यक्रम के दौरान स्थूल के समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों ने नशे से स्वयं दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज को भी नशामुक्त बनाने में सहयोग करने की शपथ ली।

टिकुरी स्टॉप डैम में मिला अज्ञात महिला का शव, शिनाख्त में जुटी जैतपुर पुलिस

मीडिया ऑडिटर, शहडोल (निप्र) जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में शिव को उस समय सनसनी फैल गई जब कुनुक नदी पर बने टिकुरी स्टॉप डैम में एक अज्ञात महिला का शव मिला सुबह ग्रामीणों ने पानी में शव देखा जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना जैतपुर थाना पुलिस को दी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस के शव काफ़ी समय तक पानी में रहने के कारण उसका पहचान तत्काल नहीं हो सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाखा की प्रक्रिया शुरू कर दी है आसपास के गाँवों में पृच्छाछ की जा रही है और ग्रामीणों से महिला के संबंध में जानकारी

जुटाई जा रही है जैतपुर थाना पुलिस ने बताया कि मुक्क का पहचान के लिए जिले और आसपास के क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की भी जांच की जा रही है पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हाल के दिनों में किसी महिला के लापता होने की सूचना तो दर्ज नहीं कराई गई है। घटना की सूचना फैलते ही टिकुरी स्पीड डैम के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों में से कोई भी महिला की पहचान नहीं कर सका पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी महिला के लापता होने की जानकारी हो तो तत्पक्ष पुलिस को सूचित करें, ताकि पहचान की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

गुंडागर्दी कर पैसे मांगने और मारपीट करने वाला आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, भेजा गया जेल



थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि वह ग्राम शिवपुर जा रहा था तभी शिवपुर निवासी प्रवेश उपाध्याय ने रास्ते में रोककर उससे शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। फरियादी द्वारा पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने उसके साथ लाठी उसकी मागपीट की और उसकी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। शिकायत

के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रवेश उपाध्याय पिता ओम प्रकाश उपाध्याय, उम्र 26 वर्ष, निवासी शिवगुप्त थाना पवार, के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2026 दर्ज कर के विवेचना शुरू की पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गुंडागर्दी करने जैसे मामलों, मारपीट करने और वाहन क्षतिग्रस्त करने के मामले में बीएसएफ की संवर्धित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया गया। इस कार्रवाई में भोजपुर जिला प्रभारी उपनिर्देशक कन्हैया सिंह बबले, प्रधान आरक्षक तनय बिन्दौर, आरक्षक शम्भू कुमार बिन्दौर और आरक्षक राकेश कुमार शर्मा को महत्वपूर्ण भूमिका रही।

**भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब,
भव्य स्वागत के लिए हिन्दू धर्म परिषद ने जताया आभार**



मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। भगवान जगन्नाथ जी की दो दिवसीय रथयात्रा में इस वर्ष श्रद्धा और आस्था का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। नगर सहित ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने

भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर
रथयात्रा में सहभागिता की
रथयात्रा के भव्य आयोजन और
ऐतिहासिक स्वागत के लिए हिन्दू
धर्म परिषद ने नगरवासियों
सामाजिक संस्थाओं, जिला
प्रशासन और पुलिस विभाग के

प्रति आधार व्यक्त किया है।
 रथयात्रा का शुभारंभ लक्ष्मणबाग से
 हुआ, जहाँ से ही बड़ी संध्या में
 श्रद्धालुओं का जनसमुह उमड़ पड़ा।
 भगवान श्री जगन्नाथ जी के
 चक्रकारों और भक्ति गीतों के बीच
 पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में
 डूब गया। रथयात्रा के निर्धारित मार्ग
 पर जगह-जगह श्रद्धालुओं ने
 पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत
 किया और अपनी धार्मिक अस्थायी
 का प्रदर्शन किया। हिन्दू धर्म परिवर्तन
 के अनुसार, इस बार रथयात्रा में
 उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने 184
 वर्षों की परंपरा में नया रिकॉर्ड
 बनाया। नगर भ्रमण के दौरान भक्तों
 का उत्साह देखते ही बन रहा था।
 बड़ी संध्या में महिला, पुरुष और

बच्चों ने स्थयात्रा में शामिल होकर भाग्यवादी जगन्नाथ के दर्शन किए और धार्मिक आयोजन को सफल बनाया। स्थयात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भंडारों और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी। मानस मंडल द्वारा आयोजित विशाल भंडारे सहित कई स्थानों पर अज्वा प्रसाद वितरित किया गया जिसे हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। भक्तों ने प्रसाद प्राप्त कर स्वयं को सौभाग्यशाली बताया और आयोजन की व्यवस्थाओं का सराहना की। स्थयात्रा के दौरान रिदम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत भागवान जी जगन्नाथ जी की महिमा से जुड़े भजनों ने पूरे वातावरण को ध्वनितमय बना दिया।

भक्ति संगीत और जयकारों से
 श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था
 का संसार हुआ स्थाना मांग में
 बज रहे भक्तों ने भक्तों का
 आध्यात्मिक आन्दन की अनुभूति
 कराई। हिन्दू धर्म परिपद के
 संस्थापक नारायण विद्याना,
 अध्यक्ष ऋषिर्षक मिश्रा, संयोजक
 सुषि मांवाजी, सह संयोजक
 उमेश कुशवाहा, मार्गदर्शक
 सी.बी. शुक्ला, डॉ. के.के. परोहा,
 डी.पी. सिंह पहार, विजय मोहन
 पारीवार, अवधेश श्रीवास्तव और
 पन्नालाल अवस्थी ने स्थाना की
 सफलता के लिए सभी सहयोगियों
 का आभार व्यक्त किया परिपद के
 पदाधिकारियों ने नगरपालिका द्वारा
 दिए गए सहयोग और सहभागिता

की विशेष रूप से प्रशंसा की उन्होंने
 कहा कि धार्मिक आयोजनों की
 सफलता में समाज के प्रत्येक वर्ग
 की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।
 नगरवासियों ने जिस उत्साह और
 श्रद्धा के साथ रथयात्रा का स्वागत
 किया, वह रैना की धार्मिक और
 सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है।
 हिंदू धर्म परिषद ने जिला प्रशासन
 और पुलिस विभाग द्वारा रथयात्रा के
 दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था
 और अन्य आवश्यक संयोग
 प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद
 ज्ञापित किया परिषद ने कहा कि
 प्रशासन और आमजन के समन्वित
 प्रयासों से इतना बड़ा धार्मिक
 आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित
 तरीके से संपन्न हो सका।

नशीली कैप्सूल तस्करी मामले में पवन उर्फ चिराग साकेत को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। नशीली कैप्सूल की तस्करि के मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सतना ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पवन उर्फ चिराग साकेत को दोषी करार दिया है विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सतना के पीठासीन अधिकारी शशिकान्त वर्मा ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है जानकारी के अनुसार यह मामला थाना सिटी कोवाली सतना के अपराध क्रमांक 83/2024 से संबंधित है। प्रकरण क्रमांक SC NDPS/53/2024 में न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी पवन उर्फ चिराग साकेत को नशीली कैप्सूल की तस्करि का दोषी पाया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और परिवहन से संबंधित मामला दर्ज किया गया था पुलिस कार्रवाई के दौरान नशीली कैप्सूल ब्रामद की गवां थीं इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच पूर्ण करने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवांओं के आधार पर अपराध पत्र सखा न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों सुने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास भुगतने के साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।

अनुसार, आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और परिवहन से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान नशीली केप्सूल बरामद की गई थीं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एफडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू करने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर अपने पक्ष रखा न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में आरोपी को 10 वर्ष की कारावास भुगतान के साथ 11 लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।

हर सरकार को अपनी कार्यशैली का एक नक्शा जमीन पर उतारना पड़ता है और इस लिहाज से सुख्खु सरकार ने अपने इरादे चिन्हित कर दिए हैं। मंडे बैठकों के दौर के बाद उच्च स्तरीय बैठकों में इरादों की कार्यशैली स्पष्ट हो रही है। मेडिकल कालेजों को श्रेष्ठ मेडिकल कालेजों के बाद अब जिला, क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों की सुध में नई इच्छा शक्ति जागृत हुई है। आज भी स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में पहली दस्तक नजदीकी अस्पतालों और खास तौर पर जिला, क्षेत्रीय या जोनल अस्पतालों में होती है। अगर जिलों की ओपीडी जिला स्तरीय अस्पतालों में संतुष्ट हो जाए, तो मेडिकल कालेज और श्रेष्ठ तथा गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं

का पैमाना तय कर पाएंगे। इसी संदर्भ में हिमाचल सरकार एमआरआई मशीनों तथा डिजिटल मैमोग्राफी सुविधा का विस्तार बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, सोलन, धर्मशाला तथा पालमपुर जैसे अस्पतालों में कर रही है। इसके अलावा मेडिकल कालेजों में 256 स्लाइस हाई एंड सीटी स्कैन तथा डिजिटल-एक्सरे मशीनें आ रही हैं। जाहिर है निरीक्षण-परीक्षण की दृष्टि से बहुत कुछ मुकम्मल होगा।

निजी क्षेत्र के सामने हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा सुदृढ़ होगा, तो मरीजों का विश्वास आज भी सरकारी अस्पतालों को अहमियत दे रहा है। हमारा मानना है कि हिमाचल को रोग विशेष के

इरादों की नई कार्यशैली

आधार पर क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों को व दक्षता को नया आयाम मिलेगा तथा राज्य स्तरीय दर्जा देना होगा। मसलन कोई एक अस्पताल अगर न्यूरो की दक्षता में संपूर्ण सुसज्जित हो तो उसे इस विषय का राज्य स्तरीय अस्पताल घोषित किया जाए। इसी तरह गैस्ट्रो, मधुमेह, यूरोलॉजी, हड्डी रोग, हार्ट व अन्य रोग विशेष के राज्य स्तरीय अस्पताल बना देने चाहिए। इससे अनुसंधान, निपुणता

हमाचल को कुछ अस्पतालों को पर्यटन से जोड़ कर देखते हुए हैल्थ टूरिज्म प्रमोोट करना होगा। मसलन कुल्लू-मनाली, शिमला व धर्मशाला के अस्पतालों में हैल्थ टूरिज्म की संभावनाएं देखी जानी चाहिए, जबकि पपरोला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के साथ-साथ कुछ अन्य आयुर्वेदिक अस्पताल

भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाएं दे सकते हैं। बहुत सारे विदेशी हिमाचल के धर्मशाला व मनाली प्रवास के दौरान डेंटल व आंख परीक्षण की सस्ती सुविधाओं से अभिभूत होते हैं। इतना ही नहीं हिमाचल के पचास साठ शहरों के लिए अब सिटी अस्पतालों की श्रृंखला में निजी निवेश प्रोत्साहित करने की योजना बनानी होगी। बहरहाल हिमाचल की सुख्खु सरकार काम, प्रगति और परियोजनाओं की निरंतरता में जो नक्शे बना रही है, उसमें सबसे अधिक निवेश और निष्कर्ष कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर निकल रहे हैं। विस्थापन से पुनर्वास तक कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार, पूरे देश के लिए एक मिसाल है। राहत के मायने मानवीय है,

साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञा इरादों की बुलंदी भी जाहिर करते हैं। अंतिम दौर में पहुंचा कार्य यह एहसास दिलाता है कि वर्तमान सरकार इस ऐतिहासिक कार्य की हर ईंट पर अपना नाम लिख रही है। दो सौ करोड़ की एक और किस्त से शामलात पर खड़े अवैध कब्जे भी मरहम-पट्टी करवा रहे हैं, ताकि गगल को बहुआयामी व्यापार का नाम देने वाले निराश होकर ठोकरें न खाएं। अब तक 2263 करोड़ का आबंटन साबित करता है कि सरकारें चाहें, तो अपने इरादों की मीनों ऊंची कर सकती हैं। अब देखना यही बाकी है कि अंतिम डेढ़ साल की परिक्रमा में सुख्खू के नेतृत्व में मिशन रिपीट होती रहे। पर आगे कौन सी बुलंदी रेखांकित होती है।

न्यायिक यथार्थता और कानून का शासन-एक सुधारात्मक दृष्टिकोण

अनिल कुमार

न्यायपालिका को किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। एक सभ्य समाज में, जहाँ कानून का शासन (Rule of La2) सर्वोपरि है, वहाँ आम नागरिक का न्याय प्रणाली पर अटूट विश्वास होता है। अदालत में न्यायाधीश केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि न्याय का साक्षात प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि न्यायलयों द्वारा दिए जाने वाले निर्णय न केवल निष्पक्ष हों, बल्कि स्थापित विधियों, संहिताओं और तय विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्णतः सटीक भी हों। जब कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या हो जाए या बुनियादी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो इसके गंभीर सामाजिक, आर्थिक और विधिक परिणाम सामने आते हैं। इस विधिक परिदृश्य को न्याय प्रणाली पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों तथा सुधार के व्यावहारिक उपायों के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है।

- (अ) विधिक त्रुटियों के सामाजिक और प्रणालीगत प्रभाव-
- न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता में कमी- एक आम नागरिक जब किसी विवाद को लेकर अदालत में आता है, तो वह यह मानकर आता है कि कानून की किताबों में जो स्थापित नियम लिखे हैं, उन्हें उसी रूप में न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन जब विधिक प्रक्रिया में स्पष्ट विधिक सिद्धांतों या विशेष अधिनियमों की प्राथमिक तालिकाओं को दरकिनार कर सरसरी तौर पर निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं, तो जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा डामगाने लगता है। समाज में यह भ्रामक संदेश जाता है कि न्याय विधिक सटीकता पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण या भाग्य पर निर्भर करता है।
 - मुकदमों की बहुलता (Multiplicity of Litigation): अधीनस्थ अदालत के किसी भी गलत या विधिक रूप से विरोधाभासी आदेश का सीधा परिणाम यह होता है कि पीड़ित पक्ष को न्याय पाने के लिए ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इससे अपीलویی मुकदमों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि होती है और न्यायलयों पर बोझ बढ़ता है। आम नागरिक का कीमती समय, धन और मानसिक शांति नष्ट होती है। जो मामला प्रारंभिक स्तर पर ही सही विधिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से निस्तारित हो सकता था, वह दशकों तक खिंचने वाला एक नया कानूनी विवाद बन जाता है।
 - विशेष कानूनों (Special Laws) की प्रभावहीनता:- विधायिका अक्सर समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं या विशेष संपत्तियों के प्रबंधन को ध्यान में रखकर विशेष अधिनियम बनाती है। स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर प्रभावी होता है।* यदि अदालतें सामान्य कानूनों की अस्थिरता के कारण विशेष अधिनियमों की प्राथमिकताओं और अनिवार्यताओं को अनदेखा कर आदेश पारित करने लगे, तो उन विशेष कानूनों का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।
 - शुद्ध कानूनी प्रश्नों को साक्ष्य पर टालना- जब कोई विवाद विशुद्ध रूप से कानून की व्याख्या या दस्तावेजों पर आधारित होता है, तो उसे त्वरित रूप से तय किया जाना चाहिए। विधिक रूप से स्पष्ट प्रश्नों को भी साक्ष्य या गवाही का विषय बनाकर भविष्य पर टाल देना एक कमजोर न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे न केवल मुकदमों की प्रक्रिया लंबी होती है, बल्कि एक अनधिकृत व्यक्ति को भी मुकदमों में बने रहने का अनुचित अवसर मिल जाता है।
 - सत (ब) न्याय की गुणवत्ता में सुधार के आवश्यक कदम- न्यायिक व्यवस्था को समाज में सर्वोपरि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए जाने आवश्यक हैं- निरंतर न्यायिक प्रशिक्षण (Continuous Judicial Training): बदलते कानूनों, विशेष राज्य अधिनियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों से अवगत रहने के लिए न्यायिक अधिकारियों एवं अधिकारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि सामान्य और विशेष कानूनों का अंतर स्पष्ट रहे।

किशन रानमुखदार भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।ऐसे समय में देश के सामने केवल आर्थिक विकास की चुनौती नहीं है,बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, कानून का प्रभावी शासन, युवाओं का भविष्य और डिजिटल युग में बदलती जीवनशैली के अनुरूप आधुनिक कानून बनाने की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। जुआ, कैसीनो और ऑनलाइन सट्टेबाजी इन्हीं विषयों में से एक है, जिसपर लंबे समय से देश में स्पष्ट, समग्र और आधुनिक नीति का अभाव दिखाई देता है। भारत में जुआ और कैसीनो के लिए कोई एक समान केंद्रीय (राष्ट्रीय) कानून नहीं है।अधिकांश मामलों में अभी भी पब्लिक गेबलिंग एक्ट,1867 (जहाँ लागू है) तथा राज्यों के अपने- अपने कानून लागू होते हैं। गोवा,सिक्किम और कुछ हद तक दमन-दीव में लाइसेंस प्राप्त कैसीनो की अनुमति है, जबकि कई राज्यों में जुआ पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबंधित है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मॉडल कानून की आवश्यकता की चर्चा समय-समय पर होती रही है।मैं एडवोकेट किशन रानमुखदार भावनानी गोदिया महाराष्ट्र अधिवक्ता होने के नाते बातना चाहूंगा कि, वर्तमान डिजिटल प्रौद्योगिकी के दौर में सोशल मीडिया,ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन कसीनो,बेटिंग ऐप्स,फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो ऐप्स, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म,एआई आधारित चैट प्लेटफॉर्म, वीडियो शेयरिंग साइट्स तथा अन्य डिजिटल माध्यमों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है।इनका सकारात्मक उपयोग शिक्षा, नवाचार और संचार के लिए उपयोगी है,लेकिन अनियंत्रित और कम उम्र में उपयोग बच्चों एवं युवाओं में नशे जैसी डिजिटल लत,मानसिक तनाव,पढ़ाई में गिरावट, आर्थिक नुकसान और सामाजिक समस्याओं का कारण बन रहा है।इसी चिंता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर कड़े प्रतिबंधों की दिशा में कदम उठाए हैं,जबकि ब्रिटेन सहित कई देशों ने आयु सत्यापन ऑनलाइन सुरक्षा और बाल संरक्षण संबंधी नियमों को सख्त बनाया है।भारत में भी डिजिटल सुरक्षा तथा अन्य ऑनलाइन गेमिंग और बच्चों की सुरक्षा को लेकर नीतिगत स्तरपर लगातार विचार-विमर्श और नियामकीय सटीकता से प्रयास जारी हैं।

साथियों, इसी क्रम में गोवा सरकार ने 16 जुलाई 2026 को अधिसूचित गोवा कसीनो (संशोधन) कानून के तहत कसीनो में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी। इसका उद्देश्य युवाओं को जुए की लत और उसके सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों से बचाना है।वर्तमान में अधिकांश भारतीय राज्यों में कसीनो या ऑनलाइन जुए के संबंध में अलग-अलग कानून हैं, लेकिन गोवा की तरह 21 वर्ष की स्पष्ट आयु-सीमा का मॉडल सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं है। कई राज्यों ने जुए पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया है,



जबकि कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर अलग-अलग नियम बनाए हैं।आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया,ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन कसीनो और अन्य व्यसन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी आयु सत्यापन, समय-सीमा, अभिभावकीय नियंत्रण तथा कठोर नियामकीय व्यवस्था लागू करें। यदि गोवा का 21 वर्ष आयु-सीमा मॉडल अन्य राज्यों में भी अपनाया जाता है,तो यह युवा पीढ़ी को डिजिटल और जुए की लत से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। साथियों 16 जुलाई 2026 से गोवा सरकार द्वारा उठाए गए दो महत्वपूर्ण कदम, 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं के कैसीनो में प्रवेश पर प्रतिबंध तथा कैसीनो उद्योग पर कर एवं नियामक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस को जन्म दिया है। यह बहस केवल गोवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रश्न पूरे भारत के सामने खड़ा करती है कि यदि किसी राज्य में कैसीनो या जुए की अनुमति है,तो क्या उसे सख्त कानून पारदर्शी कर व्यवस्था और सामाजिकउत्तरदायित्व के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए?और यदि किसी राज्य में इसकी अनुमति नहीं है,तो क्या अवैध जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए आवश्यकता से आधुनिक कानून नहीं बनने चाहिए? साथियों, गोवा भारत का प्रमुख पर्यटन राज्य है,जहाँ वर्षों से लाइसेंस प्राप्त कैसीनो संचालित हो रहे हैं। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।कैसीनो उद्योग से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है,हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन क्षेत्र को गति मिलती है। किंतु दूसरी ओर जुए की लत,आर्थिक बर्बादी, पारिवारिक विवाद,मानसिक तनाव,अपराध और युवाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव जैसी चिंताएँ भी सामने आती रही हैं। इसलिए गोवा सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आर्थिक गतिविधि

तभी स्वीकार्य है,जब वह सामाजिक उत्तरदायित्व और सख्त कानूनी निगरानी के साथ संचालित हो।21 वर्ष से कम आयु के युवाओं के कैसीनो में प्रवेश पर प्रतिबंध एक अत्यंत दूरदर्शी कदम माना जा सकता है। विश्वभर के मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस विशेषज्ञ मानते हैं कि किशोरावस्था और प्रारंभिक युवावस्था में निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह परिपक्व नहीं होती। इस आयु में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अधिक होती है और तत्काल लाभ का आकर्षण व्यक्ति को गलत निर्णयों की ओर ले जा सकता है। यदि इस अवस्था में जुए की लत लग जाए तो उसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए गोवा का यह निर्णय केवल प्रवेश रोकने का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का निर्णय है। साथियों गोवा सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण कदम कैसीनो उद्योग को अधिक उत्तरदायी कर व्यवस्था और नियामक ढाँचे के अंतर्गत लाने का है। किसी भी आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। यदि सरकार कर के माध्यम से प्राप्त राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य,खेल, नशामुक्ति, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर करती है,तो यह व्यवस्था समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। कराधान का अर्थ केवल सरकारी आय बढ़ाना नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में सटिका से पर्यटन राज्य है,जहाँ वर्षों से लाइसेंस प्राप्त कैसीनो संचालित हो रहे हैं। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।कैसीनो उद्योग से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है,हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन क्षेत्र को गति मिलती है। किंतु दूसरी ओर जुए की लत,आर्थिक बर्बादी, पारिवारिक विवाद,मानसिक तनाव,अपराध और युवाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव जैसी चिंताएँ भी सामने आती रही हैं। इसलिए गोवा सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आर्थिक गतिविधि

लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध और युवाओं में जुए की लत जैसी समस्याएँ बढ़ने की आशंका बनी रहती है। यह स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि केवल पुराने कानूनों के सहारे आधुनिक डिजिटल चुनौतियों का सटीकता से समाधान संभव नहीं है। साथियों, भारत में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जुआ और सट्टेबाजी से जुड़े अनेक कानून औपनिवेशिक काल के हैं,जबकि आज की दुनियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता,डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन गेमिंग के युग में प्रवेश कर चुकी है। आज कोई व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मोबाइल फोन से अंतरराष्ट्रीय बेटिंग वेबसाइट पर पैसा लगा सकता है।यदि सरकार केवल प्रतिबंध की नीति अपनाती है, तो अवैध गतिविधियाँ भूमिगत हो जाती हैं। यदि पूर्ण स्वतंत्रता देती है, तो सामाजिक नुकसान बढ़ सकता है।इसलिए आवश्यकता एक संतुलित नीति की है,जहाँ सटीकता से कानून भी हो,निगरानी भी हो और सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो। साथियों, मेरे विचार से भारत को अब एक मॉडल जुआ एवं कैसीनो विनियमन कानून (मॉडल गंबलिंग एंड कैसीनो रेगुलेशन लॉ) तैयार करना चाहिए। यह कानून पूरे देश पर अनिवार्य रूप से लागू न होकर राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल हो सकता है।प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्था सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसे अपनाने या संशोधित करने का अधिकार रखे।इससे देशभर में न्यूनतम कानूनी मानक (मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स) स्थापित होंगे और कानूनी अस्पष्टता दूर होगी।इस मॉडल कानून का पहला सिद्धांत होना चाहिए, युवाओं की सुरक्षा सर्वोपरि। पूरे देश में 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के कैसीनो या उच्च जोखिम वाले जुआ प्लेटफॉर्म तक पहुँचने पर प्रतिबंध होना चाहिए। आधार, पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान-पत्र के माध्यम से डिजिटल आयु सत्यापन अनिवार्य बनाया जाए। नियमों का उद्देश्य करने वाले संचालकों पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने और आपराधिक कार्रवाई का सटीकता से प्रावधान होना

चाहिए। साथियों, तीसरा व चौथा महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शी कर व्यवस्था है। कैसीनो उद्योग से प्राप्त राजस्व का निश्चित प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मानसिक स्वास्थ्य, नशामुक्ति अभियान और महिला सुरक्षा कार्यक्रमों पर खर्च करना कानून द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। इससे जनता को यह विश्वास मिलेगा कि सरकार केवल कर संग्रह नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए उसका उपयोग भी कर रही है।चौथा पक्ष डिजिटल और ऑनलाइन जुए का नियमन है। विदेशी बेटिंग प्लेटफॉर्म, अवैध ऐप और अनधिकृत वेबसाइटें भारतीय युवाओं को तेजी से आकर्षित कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय, साइबर पुलिस और राज्यों की एजेंसियों के बीच समन्वित व्यवस्था विकसित कर ऐसे प्लेटफॉर्मों पर प्रभावी नियंत्रण सटीकता से स्थापित किया जाना चाहिए। साथियों, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि जुआ सामाजिक बुराई है और इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यह विचार अपनी जगह सम्माननीय है।वहाँ दूसरा पक्ष कहता है कि जहाँ माँग मौजूद है, वहाँ पूर्ण प्रतिबंध से अवैध बाजार और संगठित अपराध बढ़ेंगे हैं। विश्व के अनेक देशों का अनुभव बताता है कि कठोर नियमन, पारदर्शी कर व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा उपाय पूर्ण प्रतिबंध की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध हुए हैं।इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, किंतु किसी भी स्थिति में अवैध जुए और डिजिटल सट्टेबाजी को कानून से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। साथियों, मेरे मत में भारत सरकार को विधि आयोग, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित करनी चाहिए। यह समिति विश्व के सफल मॉडलों का अध्ययन कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक व्यापक मॉडल कानून तैयार करे। इस कानून में 21 वर्ष की न्यूनतम आयु, डिजिटल पहचान सत्यापन, लाइसेंस प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम, जिम्मेदार जुआ कार्यक्रम, स्वेच्छिक प्रतिबंध व्यवस्था, कर पारदर्शिता, नियमित ऑडिट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पंजीकरण, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक तथा कठोर दंड जैसी व्यवस्थाएँ शामिल होनी चाहिए।

सोनम वांगचुक का त्यक्तिगत त्याग शिक्षा सुधार के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बने

जब संसद का सत्र शुरू होता है तो देश की निगाहें बहम, हंगामे और नाए कानूनों पर टिक जाती हैं। टेलीविजन चैनलों पर राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण शुरू हो जाता है और सुर्खियां यह तय करने लगती हैं कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि संसद ने कितने विधेयक पारित किए। असली सवाल यह है कि संसद ने देश के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कितनी गंभीरता से उठाया और उनके समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए।

सौरभ जैन अंकित

आज ऐसा ही एक बड़ा सवाल संसद के बाहर खड़ा है, भारत की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य क्या होगा? सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन इसी सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला रहा है। उनका संघर्ष केवल किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। यह उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता है, जो देश के करोड़ों बच्चों और युवाओं का भविष्य तय करती है। सोनम वांगचुक की पत्नी की चिंता स्वाभाविक है। हर दिन अपने पति के कमजोर होते शरीर को देखना किसी भी परिवार के लिए पीड़ादाक होगा। लेकिन यह व्यक्तिगत चिंता अब राष्ट्रीय चिंता बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास और उद्देश्य के लिए अहिंसक तरीके से व्यक्तिगत त्याग का रास्ता चुनता है, तो उसका उद्देश्य केवल सरकार को झुकाना नहीं होता। वह समाज और सत्ता की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि इस आंदोलन का



परिणाम यदि केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे या मंत्रालय में फेरबदल तक सीमित रह जाता है, तो यह एक बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को छोटा कर देगा। लोकतंत्र में मंत्रियों की जवाबदेही आवश्यक है। यदि कोई मंत्री अपने विषयों की विफलताओं की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो उससे इस्तीफे की अपेक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन व्यक्ति

बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। मंत्री आते-जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, राजनीतिक दल सत्ता में आते-जाते रहते हैं, लेकिन शिक्षा संस्थाएं और नीतियाँ लंबे समय तक समाज को प्रभावित करती हैं। इसलिए आज भारत को केवल शिक्षा मंत्री बदलने की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदलने की जरूरत है।हालभग डेढ़ दशक पहले

भारत की करीब आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की थी। अर्थशास्त्रियों ने इसे भारत का जनसांख्यिकीय लाभार्श कहा। दुनिया के किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी युवा आबादी एक असाधारण अवसर होती है। यदि इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिलें, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। नामांकन में वृद्धि हुई है। शिक्षा का विस्तार पहले की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। लेकिन केवल शिक्षा और कॉलेज बढ़ा देना शिक्षा की सफलता का प्रमाण नहीं है। असली सवाल यह है कि बच्चे और युवा वास्तव में क्या सीख रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल में अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाते। उच्च शिक्षा में भी डिग्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शोध, नवाचार, आलोचनात्मक सोच और रोजगारपरक कौशल के क्षेत्र में अभी लंबी दूरी तय करनी है। भारत यदि स्वयं को ‘विश्वगुरु’ बनाना चाहता है, तो उसे केवल अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से आगे बढ़ना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना और डिग्री देना नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य जिज्ञासा पैदा करना, तर्कशील सोच विकसित करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और युवाओं को बदलती दुनिया के लिए तैयार करना होना चाहिए। भारत की शिक्षा नीति को

राजनैतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठाना होगा। शिक्षा ऐसा विषय नहीं हो सकता जो हर सरकार के साथ बदल जाए। देश को शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। सरकार कोई भी हो, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, शोध, तकनीकी शिक्षा, मातृभाषा में सीखने, डिजिटल संसाधनों और रोजगारपरक कौशल पर निरंतर काम होना चाहिए। शिक्षा भारत का पहला वास्तविक सर्वदलीय राष्ट्रीय मिशन बन सकती है। जिस तरह देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया, उसी तरह शिक्षा को भी राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। सोनम वांगचुक का व्यक्तिगत त्याग इस बड़े उद्देश्य की शुरुआत बन सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता अपनी जगह है, लेकिन उनके आंदोलन से उठे सवाल को केवल एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह आंदोलन देश को यह सोचने का अवसर दे रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसी शिक्षा देना चाहते हैं।

चिरमिरी के विकास कार्यों पर SECL की आपत्ति, अंबेडकर भवन के बाद नालंदा परिसर निर्माण पर भी लगा ब्रेक

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। एमसीबी जिले के चिरमिरी में विकास कार्यों को लेकर नगर पालिक निगम और साइथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एसईसीएल ने पहले सर्व मांगलिक अंबेडकर भवन के निर्माण पर आपत्ति जताई थी और अब राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नालंदा परिसर परियोजना पर भी तकनीकी आधार पर रोक लगाने की बात कही है लगातार सामने आ रही इन आपत्तियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है उनका कहना है कि विकास कार्यों में बार-बार आ रही बाधाओं से शहर के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का विस्तार प्रभावित हो रहा है चिरमिरी कोयला उद्योग पर आधारित शहर है और इसका बड़ा हिस्सा एसईसीएल की लीज भूमि पर स्थित है। इसी वजह से अधिकांश सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए एसईसीएल की अनुमति आवश्यक होती है। नगर



निगम का कहना है कि विकास योजनाएं जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं, लेकिन भूमि संबंधी आपत्तियों के कारण कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। **अंबेडकर भवन निर्माण पर पहले भी जताई थी आपत्ति:** जानकारी के अनुसार करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सर्व मांगलिक अंबेडकर भवन के निर्माण कार्य पर भी एसईसीएल ने पूर्व में आपत्ति दर्ज कराई थी यह भवन शहर के लोगों के लिए विवाह, सामाजिक, सांस्कृतिक

और सामुदायिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनने वाला था स्थानीय लोगों का मानना है कि इस भवन के बनने से आम नागरिकों को निजी भवनों पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ता और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होती। हालांकि एसईसीएल ने तकनीकी और भूमि संबंधी कारणों का हवाला देते हुए निर्माण पर आपत्ति जताई जिससे परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। इस निर्णय के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध भी देखने को मिला था।

अब नालंदा परिसर पर भी

रोक: अंबेडकर भवन के बाद अब करीब 4 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित नालंदा परिसर के निर्माण पर भी एसईसीएल ने आपत्ति दर्ज की है इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने नगर पालिक निगम और स्थानीय प्रशासन को पत्र भेजकर अपनी आपत्ति से अवगत कराया है नालंदा परिसर राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है इस परिसर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, डिजिटल संसाधन और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जानी हैं। स्थानीय विद्यार्थियों का मानना है कि इस परियोजना के शुरू होने से उन्हें बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और बेहतर अध्ययन वातावरण अपने शहर में ही मिल सकेगा।

जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में नाराजगी: लगातार दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर आपत्ति के बाद जनप्रतिनिधियों

और सामाजिक संगठनों ने एसईसीएल के रवैये पर सवाल उठाए हैं उनका कहना है कि चिरमिरी जैसे खनन क्षेत्र में वर्षों से कोयला उत्पादन के माध्यम से देश और प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलता रहा है लेकिन जब शहर के विकास की बात आती है तो विभिन्न तकनीकी कारणों का हवाला देकर परियोजनाओं को रोक दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भूमि संबंधी कोई तकनीकी समस्या है तो उसका समाधान आपसी समन्वय से निकाला जाना चाहिए ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। उनका मानना है कि शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

भूमि विवाद बना बड़ी चुनौती: विशेषज्ञों का मानना है कि खनन क्षेत्रों में विकास कार्यों के दौरान भूमि स्वामित्व और लीज से जुड़े नियम अक्सर चुनौती बन जाते हैं। एसईसीएल की लीज भूमि पर किसी भी स्थायी निर्माण से पहले तकनीकी

परीक्षण और अनुमति की प्रक्रिया पूरी करनी होती है यदि निर्माण प्रस्ताव खनन गतिविधियों, सुरक्षा मानकों या भविष्य की परियोजनाओं को प्रभावित करता है तो कंपनी आपत्ति दर्ज कर सकती है। दूसरी ओर नगर निगम का तर्क है कि शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक भवनों और शैक्षणिक परिसरों का निर्माण आवश्यक है ऐसे में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और एसईसीएल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर समाधान निकालना समय की मांग है। फिलहाल नगर पालिक निगम और प्रशासन एसईसीएल की आपत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा, ताकि विकास परियोजनाएं आगे बढ़ सकें। शहर के नागरिकों की भी यही अपेक्षा है कि तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर अंबेडकर भवन और नालंदा परिसर जैसी जनहित की योजनाओं को शीघ्र शुरू किया जाए।

शिवपुरी में धान के खेत में दिखा 6 फीट लंबा मगरमच्छ, दहशत में आए ग्रामीण



मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से जंगली जीव अब आबादी और खेतों की ओर पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को ग्राम अकौदा में उस समय हड़कप मच गया जब धान की रोपाई कर रहे मजदूरों ने खेत में करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ देखा मगरमच्छ दिखाई देते ही मजदूर काम छोड़कर खेत से बाहर निकल आए और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे की है गांव के पास नदी किनारे स्थित खेत में मजदूर धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान पानी में अचानक हलचल हुई पहले उन्हें किसी बड़े जीव की मौजूदगी का अंदेश हुआ लेकिन पास जाकर देखने पर खेत के बीचों-बीच मगरमच्छ दिखाई दिया इसके बाद मजदूरों ने तुरंत खेत खाली कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर

पहुंच गए ग्रामीणों का मानना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ बहकर खेत तक पहुंच गया बारिश के मौसम में नदी और नालों से मगरमच्छ सहित अन्य जंगली जीवों के बाहर निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम तक मगरमच्छ खेत में ही मौजूद रहा। रात होने के बाद भी वह बाहर नहीं निकला जिसके चलते आसपास के गांवों से भी लोग उसे देखने पहुंचे हालांकि ग्रामीणों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी और किसी ने भी मगरमच्छ के पास जाने का प्रयास नहीं किया। बारिश के मौसम को देखते हुए प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी क्षेत्र में मगरमच्छ या अन्य जंगली जीव दिखाई दें तो उनसे दूरी बनाए रखें भीड़ न लगाएं और तत्काल वन विभाग या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दें।

मध्यप्रदेश पुलिस में सूबेदार (अ) (स्टेनो) व एसएसआई भर्ती पूरी, 438 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से रिक्त पदों स्टेनोग्राफर एवं कार्यालयीन पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सूबेदार (अ) (स्टेनो) एवं सहायक उप निरीक्षक (अ) भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है भर्ती परीक्षा- 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें कुल 438 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है हालांकि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार 13 प्रतिशत पदों का परिणाम फिलहाल होल्ड रखा गया है और इन पदों पर आगे की कार्यवाही न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। पुलिस विभाग में लगभग आठ वर्षों से

स्टेनोग्राफर एवं कार्यालयीन स्टाफ की भर्ती नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त थे इन रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2025 में पुलिस मुख्यालय ने शासन को भर्ती पर प्रस्ताव भेजा था प्रस्ताव पर त्वरित निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 100 सूबेदार (अ) (स्टेनो) तथा 400 सहायक उप निरीक्षक (अ) यानी कुल 500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी थी। अंतिम चयन सूची के अनुसार सूबेदार (अ) (स्टेनो) के 88 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 30 महिलाएं और 58 पुरुष शामिल हैं। वहीं सहायक उप निरीक्षक (अ) के 350 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया जिनमें 122 महिलाएं और 228 पुरुष हैं इस

प्रकार कुल चयनित अभ्यर्थियों में महिला उम्मीदवारों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली है भर्ती प्रक्रिया के तहत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (श्रृंखला) ने 19 सितंबर 2025 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया था आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक चली इसके बाद 17 एवं 18 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसका परिणाम 17 फरवरी 2026 को घोषित किया गया। सफल अभ्यर्थियों की 2 से 4 जून 2026 के बीच हिंदी टंकण, शीघ्र लेखन (स्टेनोग्राफी) एवं दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। लिखित और व्यावहारिक परीक्षा में प्राप्त अंकों

के आधार पर मेरिट तैयार कर श्रेणीवार अंतिम चयन सूची जारी की गई है चयनित अभ्यर्थियों को अब इकाई आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी इसके पश्चात उन्हें मध्यप्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पुलिस विभाग का मानना है कि इस भर्ती से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी प्रशिक्षित स्टेनोग्राफर और कार्यालयीन अधिकारियों की उपलब्धता से पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी और नागरिकों को सेवाएं अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

अमृत भारत योजना के तहत शिवपुरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत



मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित शिवपुरी रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को भव्य लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम

से शिवपुरी रेलवे स्टेशन का भी वचुअल उद्घाटन किया इस अवसर पर स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत

जाटव, कलेक्टर अर्पित वर्मा सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे समारोह की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई इसके बाद प्रधानमंत्री के वचुअल संबोधन और स्टेशन लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साह के साथ देखा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिवपुरी रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है स्टेशन भवन का आकर्षक पुनर्निर्माण किया गया है जिससे इसकी सुंदरता और उपयोगिता दोनों में वृद्धि हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर नए शेड लगाए गए हैं

आधुनिक बैटने की व्यवस्था की गई है तथा डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, कोच पोजिशन डिस्प्ले बोर्ड और अत्याधुनिक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम स्थापित किए गए हैं। स्टेशन परिसर के सर्कुलैटिंग एरिया का भी व्यापक विकास किया गया है यहां बेहतर पार्किंग व्यवस्था, आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शौचालय, शुद्ध पेयजल की सुविधा और बेहतर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है दिव्यांग यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए रैप, टैक्टाइल पाथ और बाधा रहित आवागमन की विशेष व्यवस्थाएं भी विकसित की गई हैं।



मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला उन्होंने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और

लोकतांत्रिक जनादेश का भी अपमान है मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने लगातार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विकास आधारित नीतियों पर भरोसा जताया है और विपक्ष उसी जनादेश पर सवाल उठा रहा है मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा को स्पष्ट समर्थन दिया है उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसका अविश्वास आखिर किस पर है-उन 25 लाख किसानों पर, जिन्हें 3100 रुपये प्रति किंटल की दर से धान खरीदी का लाभ मिला या उन 70 लाख महिलाओं पर जिन्हें महतरी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपये की सहायता मिल रही है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

किसानों को दो वर्ष का धाकड़ा बोनस, न्यू प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण और रिकॉर्ड समर्थन मूल्य का लाभ दिया गया है वहीं महतरी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को अब तक 18,800 करोड़ रुपये से अधिक का राशि वितरित की जा चुकी है उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' के रूप में आत्मनिर्भर बनाया गया है मुख्यमंत्री ने आदिवासी कल्याण के लिए तेंदुपता पारिश्रमिक में वृद्धि, चरणपादुका योजना, वनाधिकार लाभ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनम ग्रामा जैसी पहलों का उल्लेख किया साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0' को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन, तीसरे दिन 1100 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। 18 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान को प्रदेशभर में लगातार जनसमर्थन मिल रहा है अभियान के तीसरे दिन राज्य के सभी जिलों में 1100 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

किए गए जिनके माध्यम से 2 लाख 70 हजार से अधिक नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाया गया कार्यक्रमों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के साथ सामूहिक रूप से नशामुक्त जीवन अपनाने का संकल्प भी

दिलाया गया यह अभियान अब केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले चुका है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग सहित कई शासकीय विभाग अभियान में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता से अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है अभियान के तहत स्कूलों, महाविद्यालयों और छात्रावासों में विद्यार्थियों को लघु फिल्मों,

रील्स और प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। कई स्थानों पर ऑनलाइन प्लेज के जरिए प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए वहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और हाट-बाजारों में नुकड़ नाटक, जनसंवाद, रैलियां और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया सोशल मीडिया, एलईडी स्क्रीन और कचरा वाहनों के पीए सिस्टम से माध्यम से भी व्यापक स्तर पर संदेश प्रसारित किए गए। अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में कई नवाचार भी देखने

को मिले इंदौर में करीब 1.75 लाख लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाया गया, जहां जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई, 'नाकों हेल्पलाइन' शुरू की गई और विशेष जागरूकता गीत लॉन्च किया गया बालाघाट में मैराथन रैली आयोजित कर 'नशा मुक्ति ऐप' के जरिए 430 'नशा मुक्ति



मित्र' बनाए गए ग्वालियर में 45 थाना क्षेत्रों में नुकड़ नाटकों और जागरूकता रथों के माध्यम से 17 हजार से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचा, जबकि छिंदवाड़ा, कटनी, धार, जबलपुर, बैतूल, खरगोन और पन्ना सहित कई जिलों में स्थानीय स्तर पर रैलियां, विशेष अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़कर अपने परिवार और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' के जन-जन का आंदोलन बनाने में सहयोग करें।

स्मार्ट मीटर और महंगे बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस का घर-घर अभियान शुरू

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमिटी ने शनिवार से रायपुर में व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें स्मार्ट मीटर हटाने या बदलने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करा रहे हैं अभियान की शुरुआत लाखे नगर स्थित बिजली कार्यालय से की गईइसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न वार्डों और कॉलोनियों में पहुंचे जहां उन्होंने लोगों से स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और उनकी शिकायतें सुनीं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना

में काफी बढ़ गए हैं जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जनसंपर्क अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें भी स्मार्ट मीटर के कारण अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं या अन्य तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वे आवेदन पत्र भरकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं कांग्रेस का कहना है कि एकत्रित आवेदनों को सरकार और बिजली विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए नेताओं ने बिजली उपभोक्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी।



मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर शहर के गांधीनगर क्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे एक मकान में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण घर के अंदर चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। मकान के निचले हिस्से में प्लास्टिक का सामान और पानी की टंकियों से भरा गोदाम होने के कारण आग तेजी से फैल गई। चार्जिंग पर लगी स्कूटी से शुरू हुई आग जानकारी के अनुसार, गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी सचिन जैन के मकान में रात के समय अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी। शुरूआत में आग स्कूटी के आसपास लगी, लेकिन कुछ ही समय में उसने पूरे निचले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में प्लास्टिक का सामान बड़ी मात्रा में रखा होने से आग तेजी से फैलती चली गई। फायर टीम ने परिवार को सुरक्षित निकाला मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। राहत और बचाव टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। फायर टीम ने मकान की पहली मंजिल पर मौजूद परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से लगातार प्रयास किया। करीब एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। हालांकि, इस दौरान मकान के निचले हिस्से में रखा प्लास्टिक का सामान और गोदाम का अन्य सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान प्रारंभिक आकलन के अनुसार, इस अग्निकांड में करीब 5 लाख रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग में गोमंज में रखा सामान और मकान के निचले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।



मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। इटारसी के बाद अब जिला मुख्यालय में भी चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। कलवाली थाने से 300 मीटर दूर शहर के बीच बाजार, अमर चौक पर शुक्रवार रात शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना से सनसनी फैल गई। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। देर रात को पुलिस ने कেস दर्ज किया। चाय पीने के दौरान मांगे रुपए, फिर किया हमला प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले अरमान खान निवासी जुमेराती रात 9 बजे दोस्त अल्फेज के साथ राजू टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे। तभी वहां खड़े शेख इमरान उर्फ रानू निवासी फूटा कुंआ ने शराब पीने के लिए 1 हजार रुपए मांगे। अरमान के मना करने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगा और जेब से चाकू निकालकर हमला कर दिया। पहला वार पेट पर, दूसरा अंगूठे पर हसले में अरमान के पेट और उल्टे हाथ के अंगूठे पर चोट आई। खून तेजी से बहने लगा। साथियों ने उसे पहले कोतवाली थाना ले गए, जहां से पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस कार्रवाई रात 11.15 बजे एसआई अनुज बघेल ने अस्पताल में घायल के बयान लिए। इसके बाद आरोपी शेख इमरान के खिलाफ अड़ीबाजी और हमले का केस दर्ज किया गया। टीआई गौरव सिंह बुदिला ने बताया घायल की हालत सामान्य है। आरोपी की तलाश में टीम लगी है। जिले में बह रही चाकूबाजी की घटनाएं पिछले 1 सप्ताह में इटारसी, पथरीटा में चाकूबाजी की 8 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। एक वारदात में हत्या भी हुई थी।

खुरई में मोबाइल चलाते किसान पर सियार का हमला हाथ में आई चोट, वन विडायग ने कहा- अकेले घर से न निकले



मीडिया ऑडीटर, बीना (निप्र)। खुरई के बेरी गांव में शुक्रवार रात एक किसान पर सियार ने हमला कर दिया। मोबाइल चलाते समय हुए इस हमले में किसान घायल हो गया, जिसे खुरई के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेरी गांव निवासी वकील सिंह राजपूत (42) ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वे रात में टहलने निकले थे। गांव के पास मोबाइल चला रहे थे, तभी अचानक एक सियार ने उन पर हमला कर दिया राजपूत के अनुसार, सियार ने उन पर दो बार हमला किया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। जब वे खुद को बचाने के लिए डंडा ढूँढ रहे थे, तब सियार ने तीसरी बार हमला किया। हाथ में डंडा आने के बाद सियार वहां से भाग गया। इस दौरान वकील सिंह राजपूत के हाथों में चोटें आई हैं।

सीहोर में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने वाले गुंडे का जुलूस आष्टा पुलिस ने निकाला, आरोपी पर 16 गंभीर केस दर्ज

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। आष्टा थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, मारपीट और अड़ीबाजी करने वाले मुख्य आरोपी श्याम पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का सड़क पर जुलूस निकाला और उसे थाने तक लेकर गई। आरोपी पर अड़ीबाजी, बलवा, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे 16 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खाने और धमकाने का आरोप मामला आष्टा थाना क्षेत्र के ग्राम कोठी का है। रेस्टोरेंट संचालक मुकेश वर्मा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि अमल्लाह गांव निवासी श्याम पटेल अक्सर उसके रेस्टोरेंट पर आता था और बिना पैसे दिए खाना खाता था। शिकायत के अनुसार, जब भी उससे खाने के पैसे मांगे जाते थे तो वह धमकी देकर विवाद करता था। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचकर हंगामा किया। 25 हजार रुपए मांगने के बाद की मारपीट मुकेश वर्मा के अनुसार, हाल ही में श्याम पटेल अपने पांच साथियों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा था। आरोप है कि उसने वहां 25 हजार रुपये की मांग की। जब रेस्टोरेंट संचालक ने



रुपये देने से इनकार किया तो श्याम पटेल और उसके साथियों ने मुकेश वर्मा तथा उनके बेटे विनय के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की।

रेस्टोरेंट में तोड़े कांच और एसी: मारपीट के दौरान आरोपियों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी की। आरोप है कि उन्होंने वहां लगे कांच और एसी सहित अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया। घटना के

बाद मुकेश वर्मा ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने दर्ज किया मामला, शुरू की तलाश फरियादी

शादी के 6 महीने बाद युवती ने सुसाइड किया आखिरी कॉल मां को किया, पति पर प्रताड़ना के आरोप; 17 की उम्र में लव मैरिज की थी

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा के खालवा थाना क्षेत्र के मलगांव में शादी के महज छह महीने बाद एक 18 वर्षीय नवविवाहिता ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान कृष्णाबाई निवासी खारी टिमरनी, जिला हदय के रूप में हुई। उसका विवाह करीब छह महीने पहले मलगांव निवासी मुकेश पिता बली नायक से हुआ था। परिजनों के अनुसार, कृष्णाबाई ने करीब साढ़े 17 वर्ष की उम्र में घर से मुकेश के साथ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे थे। वर्तमान में उसकी उम्र 18 वर्ष थी। आरोप-शराब, जुआ और मारपीट से बेटी परेशान थी कृष्णाबाई की मां संतराबाई का आरोप है कि शादी के



कुछ समय बाद से ही मुकेश का व्यवहार बदल गया था। वह शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था और आए दिन कृष्णाबाई के साथ मारपीट करता था। आरोप है कि वह बेटी को मायके वालों से बात तक नहीं करने देता था। उसका मोबाइल फोन भी अपने पास रख लेता था ताकि वह परिवार से संपर्क न कर सके। परिजनों का यह भी आरोप है कि मुकेश कृष्णाबाई को बांझ कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित

करता था। लगातार प्रताड़ना के कारण वह तनाव में रहने लगी थी। परिवार के अनुसार, कई बार दोनों पक्षों के बीच समझाइश भी कराई गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बेटी की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय पहले उसे मुंबई में रहने वाले रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया था। करीब पांच दिन पहले ही वह वापस अपने ससुराल मलगांव लौटी थी। मरने से पहले मां को किया फोन परिजनों ने बताया

कि गुरुवार को कृष्णाबाई ने अपनी मां को फोन कर कहा कि उसने जहरीली दवा पी ली है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग सक्रिय हुए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कृष्णाबाई के भाई भगवानदास ने भी बहन के पति पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मुकेश शराब के नशे में आए दिन विवाद करता था और बहन के साथ मारपीट करता था। परिवार का आरोप है कि लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर कृष्णाबाई ने यह कदम उठाया। निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग मायके पक्ष ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी पति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रताड़ना बंद हो जाती तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। खालवा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करारकर परिजनों को सौंप दिया है।

बुरहानपुर पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति अभियान 15 स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित



मीडिया ऑडीटर, बुरहानपुर (निप्र)। बुरहानपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत जिले भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।। पुलिस अधीक्षक आशुतोष

दुग्गुभावाों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रील्स और शॉर्ट फिल्में दिखाई गईं, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इसके अतिरिक्त, 'नशे से दूरी है जरूरी' और 'हमारा है यही संकल्प, नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश' जैसे संदेशों वाले पंपलेट भी वितरित किए गए। इस अभियान में कोतवाली, शिकारपुरा, लालबाग, गणपतिनाका, नेपांगर, निंबोला, शाहपुर, धूलकोट चौकी, देडतलाई चौकी, महिला थाना, अजाक और नावरा चौकी सहित सभी संबंधित इकाइयों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन स्थानों पर छात्रों, ग्रामीणों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए।

रतलाम में 2.90 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त जावरा पुलिस ने दो तरकरों समेत सप्लायर को दबोचा, रिमांड पर पूछताछ जारी

मीडिया ऑडीटर,रतलाम (निप्र)। रतलाम जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के तहत जावरा शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29.05 ग्राम एमडी (सब्) ड्रग्स बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक ड्रग्स सप्लायर भी शामिल है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2.90 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई जावरा शहर थाना प्रभारी दीपक मंडलौई ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने शुक्रवार को अजमेरी गेट-भीमाखेड़ी चौराहा रोड स्थित सीताराम बाग के सामने घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने हुसैन खान (26), पिता



असलम खान पठान, निवासी ग्राम राकोदा, थाना पिपलोदा, को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी लेने पर उसके

कब्जे से 29.05 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुईं। पूछताछ में सामने आया सप्लायर का नाम प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी हुसैन

खान था। साथ ही पूरे ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जावरा शहर थाना पुलिस ने दो तस्करों के पास 29.05 ग्राम एमडी पकड़ी है। जिसकी कीमत 2.90 लाख रुपए है। पुलिस ने एमडी बेचने वाले सप्लायर को भी पकड़ा है। जावरा शहर थाना प्रभारी दीपक मंडलौई ने बताया मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को अजमेरी गेट भीमाखेड़ी चौराहा रोड सीताराम बाग के सामने जावरा से आरोपी हुसैन खान (26) पिता असलम खान पठान निवासी ग्राम राकोदा थाना पिपलोदा को अवैध मादक पदार्थ 29.05 ग्राम सब् ड्रग्स के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी हुसैन खान ने बताया कि उसने एमडी एक अन्य व्यक्ति से खरीदी है।

कोच का निर्देश, धैर्य और फोकस जापान ओपन फाइनल में पहुंचने की वजह: पीवी सिंधु



नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की पीवी सिंधु ने शनिवार को जापान ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में पहुंचने का श्रेय फोकस, धैर्य और अपने कोच से मिले निर्देशों को दिया। सिंधु ने सेमीफाइनल में चीन की चेन युफेई को हराकर जापान ओपन के फाइनल में जगह बनाई

है। सिंधु टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिमनैजियम में 21-19, 15-10 से आगे चल रही थीं। इसी समय पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण रिटायर हो गईं। युफेई के रिटायर होते ही सिंधु अपने पहले बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 फाइनल और दिसंबर 2024 के बाद अपने पहले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल मुकाबले में पहुंच गईं। मैच के बाद सिंधु ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के खिलाफ शुरुआती रैली से ही एकाग्रता बनाए रखना उनके गेम प्लान का मुख्य हिस्सा था। ओलंपिक डॉट कॉम से बात करते हुए सिंधु ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मेरे लिए, पहले गेम से ही हर मैच बहुत मायने रखता था और आज का मैच खासकर, शुरू से ही फोकस करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप टॉप रैंक वाले खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, तो हर अंक मायने रखता है। पहला गेम जीतना सच में बहुत मायने रखता है।' उन्होंने कहा, 'मैं पूरी तरह खेल पर केंद्रित थी। मेरे कोच कहते रहे, क्योंकि मैं पहले गेम में आगे चल रही थी और चेन युफेई काफी करीब आई थी, इसलिए और ध्यान देना जरूरी था। कभी-कभी जब आप आगे चल रहे होते हैं और अंक गंवा देते हैं, तो आप अचानक निराश हो जाते हैं, यह सोचकर कि ये अंक क्यों जा रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी भावनाएं आती हैं। मेरे कोच कह रहे थे कि बस अगले पॉइंट पर फोकस करो। इससे सच में मदद मिली।' सिंधु के लिए शुरुआती गेम मुकाबले का सबसे अहम दौर साबित हुआ। शुरुआत में आगे निकलने के बाद, सिंधु को दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी के जोरदार मुकाबले का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि वह सेट 21-19 से जीत जाती, जिससे उन्हें दूसरे गेम में अहम बढ़त मिल गई। भारतीय खिलाड़ी ने चोट के कारण चेन के रुकने तक उन्होंने दूसरे गेम को कैसे खेला। उन्होंने कहा कि दूसरे सेट में भी, लंबी रैलियां हुईं, खासकर पहले गेम में- वो लंबी रैली जो हुई और मैंने उसे जीत लिया, वो मेरे लिए वो अंक पाने के लिए बहुत जरूरी थी। दूसरे गेम में भी, मेरे लिए पहले पॉइंट से ही फोकस करना जरूरी था क्योंकि वो काफी बराबर चल रहा था। भले ही मैं 2 पॉइंट से आगे थी, वो कवर कर रही थी और वापस आ रही थी। 11 पॉइंट के बाद, मैं 3-4 पॉइंट की लीड बनाए हुए थी। बदकिस्मती से, उसे रिटायर होना पड़ा। सिंधु का रविवार को फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से सामना होगा। वर्ल्ड नंबर 3 यामागुची तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं।

लॉर्ड्स में कोहली-रोहित की जोड़ी रचेगी इतिहास, नाम जुड़ेगी बड़ी उपलब्धि



नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेला जाना है। तीसरे वनडे में मैदान पर उतरने के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। दरअसल, लॉर्ड्स में रोहित और कोहली एक साथ मिलकर भारत की ओर से 400वां इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। कोहली-रोहित की जोड़ी इस मुकाम तक पहुंचने वाली भारत की ओर से पहली जोड़ी बनेगी। यह दोनों इस खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। सचिन-द्रविड़ ने भारत के लिए एक साथ मिलकर 391 मुकाबले खेले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने के नाम है।

संगकारा और जयवर्धने ने एक साथ श्रीलंका के लिए 550 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। वह दो एकदिवसीय मुका लों में अब तक सिर्फ 37 रन ही बना सके हैं। दूसरे वनडे में 47 गेंदों का सामना करने के बाद रोहित महज 26 रन ही बना सके थे और अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे थे। रोहित के भविष्य को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉर्ड्स वनडे को रोहित के करियर का आखिरी मैच बताया जा रहा था। हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हालांकि, दूसरे वनडे में विराट कोहली अच्छी लय में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुश्किल हालातों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों में 65 रनों की दमदार पारी खेली थी।

लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं:

BCCI सचिव देवजीत सैकिया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। सैकिया ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी मैच रोहित शर्मा के वनडे करियर का अंतिम मैच हो सकता है। बीसीसीआई सचिव ने इन खबरों को केवल अटकलबाजी बताया। बीसीसीआई सचिव सैकिया ने आईएनएस से कहा, 'रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। बोर्ड के स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। सैकिया ने कहा है कि रोहित भारतीय वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और जब तक वह टीम का हिस्सा हैं, तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। लॉर्ड्स का मुकाबला रोहित शर्मा के वनडे करियर का अंत नहीं है।

खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी मैच रोहित शर्मा के वनडे करियर का अंतिम मैच हो सकता है। बीसीसीआई सचिव ने इन खबरों को केवल अटकलबाजी बताया। बीसीसीआई सचिव सैकिया ने आईएनएस से कहा, 'रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। बोर्ड के स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। सैकिया ने कहा है कि रोहित भारतीय वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और जब तक वह टीम का हिस्सा हैं, तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। लॉर्ड्स का मुकाबला रोहित शर्मा के वनडे करियर का अंत नहीं है।

'यह यकीन करना मुश्किल है',

सचिन-कोहली ने सर गैरी सोबर्स के निधन पर लिखा भावुक पोस्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स के 89 साल की उम्र में बारबाडोस में निधन के बाद क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। दुनिया भर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व और मौजूदा क्रिकेटर्स ने खेल में सोबर्स के बेमिसाल योगदान को याद किया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने भी सोबर्स को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक पोस्ट लिखा है। सोबर्स के साथ अपने करियर के दौरान कई यादगार पल बिताने वाले सचिन तेंदुलकर ने उनके साथ बने निजी रिश्तों को याद किया। 2003 वनडे वर्ल्ड कप से लेकर लंदन में अपनी आखिरी मुलाकात तक के पलों को याद करते हुए भारत के महान बल्लेबाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'यह यकीन करना बहुत मुश्किल है कि सर गैरी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन यादों को याद कर रहा हूँ जो हमने वषों में साथ बनाई थीं। 2003 वर्ल्ड कप में उनका मुझे 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' की ट्रॉफी देना हो या शतक का मील का पत्थर छूने पर उनकी तारीफ भरे शब्द।' उन्होंने आगे लिखा, 'वह हमेशा बहुत ही विनम्र और अच्छे स्वभाव वाले इंसान रहे। मेरा मन बार-बार उस समय की ओर जाता है जब हम कुछ साल पहले लंदन में मिले थे। हम बस बैठकर खेल के बारे में बातें कर रहे थे, और अब यह बात मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। वह सच में बेमिसाल थे। उनकी बहुत याद आएगी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सर गैरी।' सोबर्स ने 2003 वनडे वर्ल्ड कप में भारत के उपविजेता रहने के बाद तेंदुलकर को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड दिया था। वहीं, सचिन द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में 'शतकों



का शतक' पूरा करने पर भी सोबर्स ने उन्हें सम्मानित किया था। विराट कोहली ने भी श्रद्धांजलि देते हुए सोबर्स को क्रिकेट की महानतम हस्तियों में से एक बताया, जिनका प्रभाव उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक बना रहेगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'क्रिकेट ने अपनी महानतम हस्तियों में से एक को खो दिया है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सर गारफील्ड सोबर्स। आपकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।' भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी सोबर्स के परिवार और क्रिकेट जगत के प्रति संवेदन व्यक्त करते हुए ऐसी ही भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने लिखा, 'सर गारफील्ड सोबर्स के निधन से बहुत दुख हुआ। एक सच्चे दिग्गज जिनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उनके परिवार और क्रिकेट जगत के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले।' भारत के ऑलराउंडर शाहुल ठाकुर ने सुनील गावस्कर के साथ हाल ही में हुई बातचीत को याद करते हुए कहा कि इस महान बल्लेबाज ने सोबर्स के निधन की खबर से कुछ दिन पहले ही उनकी बहुत तारीफ की थी।

राष्ट्रीय शूटर दमयंती सेन 48 घंटे बाद घर लौटीं

लापता होने की वजह तलाश रही पुलिस

कोलकाता, एजेंसी। पिछले 48 घंटों से लापता पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय स्तर की शूटर दमयंती सेन शनिवार सुबह सुरक्षित अपने घर लौट आईं। हालांकि, उनके दो दिनों तक लापता रहने की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। परिवार और जांच एजेंसियों की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार, दमयंती सेन गुरुवार दोपहर अपने घर से कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए निकली थीं। उनके पास उस समय मोबाइल फोन भी था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटीं। काफी देर तक संपर्क न होने पर परिवार ने उनकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उन्हें तलाशने के लिए विशेष जांच शुरू की गई। शनिवार सुबह हावड़ा जिले के रामकृष्णपुर फेरी जेटी के पास सुबह टहलने वाले कुछ लोगों ने दमयंती को बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के घूमते हुए देखा। लोगों ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उनके परिवार को सूचना दी। इसके बाद उनके पिता ध्रुवज्योति सेन मौके पर पहुंचे और बेटी को सुरक्षित घर ले आए। दमयंती के लापता रहने के दौरान उन्हें दो अलग-अलग स्थानों पर देखा गया था। सबसे पहले गुरुवार को हावड़ा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में वह प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच के बीच घूमती हुई नजर आई थीं।



स्पेन के लिए आई राहत भरी खबर

फाइनल मैच के लिए फिट हुए लामिन यामल



न्यूयॉर्क, एजेंसी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले स्पेन के लिए राहत भरी खबर आई है। अर्जेंटीन के खिलाफ होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए टीम के युवा स्टार फॉरवर्ड लामिन यामल अब पूरी तरह फिट हैं। इस बात की जानकारी टीम के हेड कोच लुइस डे ला फुएते ने दी है। 19 वर्षीय यामल को फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के बाद लंगड़ाते हुए देखा

गया था। उस मुकाबले में स्पेन ने 2-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई थी। चोट के कारण यामल गुरुवार को टीम के अभ्यास सत्र में शामिल नहीं हुए थे। इससे उनके फाइनल खेलने को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि, डे ला फुएते ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि यामल को जोरदार चोट लगी थी, जिससे काफी दर्द हो रहा था। एहतियात के तौर पर उन्हें आराम दिया गया था।



स्मृति मंधाना

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। महिला टीम के मैचों को देखने के लिए अब फैस बड़ी संख्या में स्टेडियम में जुड़ते हैं और मोबाइल, टीवी पर भी चिपके रहते हैं। इसकी एक वजह बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना हैं, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से फैस के बीच महिला क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। फैस मैदान में 'मंधाना' नाम के नारे लगाते हैं, जो इस खिलाड़ी की बड़ी सफलता है। लोकप्रियता के मामले में मंधाना देश के शीर्ष पुरुष क्रिकेटर्स को टक्कर देती हैं। स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ था। मंधाना के पिता और भाई दोनों क्रिकेटर रहे थे। इसका असर उन पर पड़ा, और उन्होंने ने भी इसी खेल में आगे बढ़ने का फैसला किया। मंधाना ने एक साक्षात्कार में बताया था कि उनके पिता को बाएं हाथ के बल्लेबाज पसंद थे, इसलिए उन्होंने बाएं हाथ की बल्लेबाज बनने का फैसला किया। 9 साल की उम्र में मंधाना को महाराष्ट्र अंडर-15 टीम में जगह मिली थी और 11 साल की उम्र में वह राज्य की अंडर-19 टीम में शामिल हुईं। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही मंधाना के लिए साल 2013 बड़ी सफलता लेकर आया। 5 अप्रैल 2013 को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में डेब्यू से अपने

अपनी दमदार बल्लेबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट में फूंकी नई जान

अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। डेब्यू के बाद से मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम में तीनों फॉर्मेट में सबसे अहम खिलाड़ी बनी हुई हैं। वह टीम की सबसे बड़ी मैच विजेता खिलाड़ियों में से एक हैं। मंधाना के करियर पर गौर करें तो उन्होंने टेस्ट में 2014 में, वनडे में 2013 और टी20 में 2013 में डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में मंधाना ने 9 टेस्ट की 16 पारियों में 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 788 रन, 120 वनडे की 120 पारियों में 14 शतक और 35 अर्धशतक लगाते हुए 5,411 रन और 171 टी20 की 165 पारियों में 1 शतक और 35 अर्धशतक लगाते हुए 4,538 रन बनाए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की पोस्टर गर्ल मानी जाने वाली मंधाना ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी के बाद आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड दो बार जीतने वाली दूसरी क्रिकेटर हैं। मंधाना वनडे फॉर्मेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाली (50 गेंदों पर) बल्लेबाज हैं। वनडे फॉर्मेट में वह मिताली राज के बाद भारत की तरफ से दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज हैं। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज हैं। वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक के मामले में मंधाना दूसरे स्थान पर हैं। महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मार्तण्ड स्कूल और सेंट्रल लाइब्रेरी निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश, 15 अगस्त तक लाइब्रेरी भवन के लोकार्पण की तैयारी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने शनिवार को शहर में चल रहे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया उन्होंने शासकीय मार्तण्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 में निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तय समय के अनुसार निर्माण पूरा कराया



जाए जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें इस अवसर पर पूर्व पार्षद सतीश सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल मिश्र, विद्यालय के प्राचार्य सुदामालाल गुप्ता सहित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सेंट्रल लाइब्रेरी भवन का भी लिया जायजा: इसके बाद



लिए अध्ययन की सुविधाओं को बेहतर बनाना आवश्यक है लाइब्रेरी में पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन के साथ ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए उन्होंने ई-लाइब्रेरी के लिए आवश्यक उपकरण कंप्यूटर तथा ऑपरेटर की व्यवस्था भी समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए उप

मुख्यमंत्री ने लाइब्रेरी में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और सुविधाओं की जानकारी ली उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से ज्ञान प्राप्त का चलन तेजी से बढ़ रहा है इसलिए विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से जोड़ना जरूरी है 123 करोड़ 69 लाख की लागत से तैयार हो रहा भवन सेंट्रल लाइब्रेरी के नवीन भवन का निर्माण पुनर्धनत्वोकरण योजना के तहत 23 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। भवन में विद्यार्थियों के लिए 160 सीटों की पठन-पाठन व्यवस्था आधुनिक फर्नीचर और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे निरीक्षण के दौरान पार्षद समीर शुक्ला, राजगोपालाचारी मिश्र लोक निर्माण विभाग एवं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों परियोजनाओं का कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि आमजन और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।

गोपाल नगर वार्ड-43 की सड़क बद्दहाल, बारिश में कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर रहवासी



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड नंबर 43 गोपाल नगर में सड़क की बद्दहाल स्थिति से रहवासी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग किए जाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है जिससे लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से आवागमन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है वार्डवासियों के अनुसार, सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। गड़ौ और खराब मार्ग के कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही

है। थोड़ी सी बारिश के बाद सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संबंध में वार्ड पार्षद, नगर निगम अधिकारियों और उपयंत्री को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में किसी तरह आवागमन हो जाता है, लेकिन बरसात में हालात बेहद खराब हो जाते हैं रहवासियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की अनदेखी के कारण उन्हें वर्षों से परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करते हुए सड़क का जल्द निर्माण कराने की मांग की है, ताकि वार्ड के लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

रीवा कांग्रेस की विस्तारित बैठक में संगठन मजबूती, भवन निर्माण और जनहित के मुद्दों पर बनी रणनीति

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण एवं शहर की विस्तारित बैठक स्थानीय होटल सेलीब्रेशन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष (ग्रामीण) इंजी. राजेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में सेमरिया विधायक अभय मिश्रा एवं रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे बैठक में संगठन विस्तार कांग्रेस कार्यालय के नए भवन निर्माण तथा किसानों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे शीघ्र पूरा कर लोकार्पण कराया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रमों से भवन निर्माण में आर्थिक सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि रहलू गांधी



की मंशा के अनुरूप जिला से बृथ स्तर तक संगठन सृजन अभियान के तहत समितियों का गठन और सत्यापन पूरा हो चुका है। अब मंडलम स्तर पर बैठकों के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा बैठक में अनुशासन पर

कांग्रेस गांव-गांव तक ले जाएगी किसानों को खाद-बीज की कमी बिजली व्यवस्था और स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का निर्णय लिया गया चेतावनी दी गई कि एक सप्ताह में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने पर जिलेभर में आंदोलन किया जाएगा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन कराया, जिन्हें उपस्थित पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से पारित किया कार्यक्रम का संचालन जिला संगठन महासचिव एडवोकेट रवि तिवारी ने किया तथा स्वागत जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष अशोक पटेल ने किया बैठक में विधायक अभय मिश्रा, प्रदेश पदाधिकारी, महिला कांग्रेस युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भनिगवां स्कूल में मध्यान्ह भोजन योजना पर सवाल वर्षों से संचालन कागजों में होने का आरोप



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भनिगवां में मध्यान्ह भोजन योजना को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से मध्यान्ह भोजन व्यवस्था नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही है और योजना का लाभ विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है मामले में प्रभारी प्राचार्य और स्वसहायता समूह संचालक की मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं जानकारी के अनुसार, शासन द्वारा विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन योजना संचालित की जा रही है, लेकिन भनिगवां विद्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और सुर्गों का आरोप है कि कई वर्षों से भोजन व्यवस्था केवल रिकॉर्ड में संचालित



दिखाई जा रही है जबकि वास्तविक स्थिति में बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है बताया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी अपने घरों से भोजन लेकर स्कूल आते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भोजन से वंचित रह जाते हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है आरोप है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए जिम्मेदार समूह द्वारा पिछले वर्ष भोजन बनाया गया था लेकिन वर्तमान सत्र में अभी तक व्यवस्था शुरू नहीं की गई। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी मध्यान्ह भोजन संचालन में लापरवाही बरतने

की बात सामने आई है स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण और जांच नहीं किए जाने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा विद्यार्थियों को नियमानुसार भोजन उपलब्ध कराने की मांग की है हालांकि इस मामले में विद्यालय प्रबंधन और संबंधित स्वसहायता समूह की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ध्वनि प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई: 130 मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चला रोड रोलर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 130 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों को सेरेआम रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया यह कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई पुलिस का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है यातायात थाना प्रभारी अजिता शर्मा एवं सूबेदार अखिलेश कुशवाह ने बताया कि शहर में लगातार ऐसे दोपहिया वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिनमें नियमों के विरुद्ध मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए गए हैं जांच अभियान के दौरान जब्त किए गए करीब 130 साइलेंसरों को सार्वजनिक रूप से



रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया ताकि लोगों के बीच यह स्पष्ट संदेश जाए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी सूबेदार अखिलेश कुशवाह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालानी कार्रवाई करना नहीं बल्कि युवाओं

को जागरूक करना भी है उन्होंने कहा कि बुलेट और अन्य दोपहिया वाहनों में लगाए जाने वाले अवैध साइलेंसर तेज एवं पटाखों जैसी आवाज उत्पन्न करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है और आम नागरिकों बुजुर्गों तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लगातार तेज शोर मानसिक तनाव सुनने की क्षमता में कमी और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है पुलिस ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त करने के साथ संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला गया है रीवा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें साथ ही स्पष्ट किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

उप मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल, संतों का लिया आशीर्वाद और शोकाकुल परिवारों से की मुलाकात



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल शनिवार को रीवा में आयोजित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने धार्मिक आयोजन में सहभागिता करते हुए संतों का आशीर्वाद प्राप्त

किया तथा कई स्थानों पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। **जैन संतों के मंगल प्रवेश कार्यक्रम में हुए शामिल:** उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल आचार्य विजयसागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य समयसागर महाराज जी एवं अतुल सागर जी



महाराज के भव्य मंगल प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए उन्होंने जैन संत मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संतों का सान्निध्य समाज को सदाचार, संयम और कल्याण का मार्ग दिखाता है ऐसे

धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाते हैं। **अखंड रामचरित्र मानस पाठ में की सहभागिता:** उप मुख्यमंत्री ने विजय मिश्रा के

निवास स्थल पर आयोजित अखंड रामचरित्र मानस पाठ में भागीदारी निभाई उन्होंने धार्मिक आयोजन में शामिल होकर श्रद्धा एवं आस्था व्यक्त की। **शोकाकुल परिवारों से मिलकर दी सात्वना:** इसके बाद उप मुख्यमंत्री शुक्ल सगर स्थित विनायक प्रसाद तिवारी के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी दिवंगत माता जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें सात्वना दी उप मुख्यमंत्री ने कुबेर तालाब में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष स्वर्गीय राघवचरण मिश्र को श्रद्धासमन अर्पित किए उन्होंने स्वर्गीय मिश्र

के सामाजिक एवं संगठनात्मक योगदान को याद किया उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर कमलेश सचदेवा की बहन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की इसके बाद उन्होंने मिनर्वा अस्पताल पहुंचकर उपचार करा रहे अमित कोहली के पिता जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली उन्होंने चिकित्सकों से उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त करते हुए मरीज के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की दिवंगत के कार्यक्रमों के दौरान उप मुख्यमंत्री ने धार्मिक आस्था सामाजिक संवेदनशीलता और जनसंपर्क का परिचय देते हुए विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने छिपकली के काटने का जताया संदेह

मीडिया ऑडीटर, मऊंज (निप्र)। मऊंज जिले के हनुमान थाना क्षेत्र के जड़कुड़ गांव में 36 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि महिला को रात में सोते समय छिपकली ने काट लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई हालांकि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा मृतका की पहचान फूलकली बैगा (36)पत्नी रामसुंदर बैगा, निवासी जड़कुड़ गांव के रूप में हुई है परिजनों के अनुसार शुक्रवार रात भोजन करने के बाद वह सो गई थीं। देर रात उन्होंने शरीर में बेचैनी की शिकायत की। घरवालों का कहना है कि इसी दौरान उन्हें किसी छिपकली ने काट लिया था जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई उ प रिज न उन हें तत्काल सिविल अस्पताल मऊंज लेनर पहुंचे जहां शनिवार दोपहर उपचार के दौरान उनकी



मौत हो गई सूचना मिलते ही पिंपराही चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. संजय पटेल ने बताया कि परिजनों ने छिपकली के काटने की जानकारी दी है लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम और अन्य जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा वहीं पिंपराही चौकी प्रभारी ज्ञानेंद्र पटेल ने बताया कि मर्ग कायम कर मापले की जांच शुरू कर दी गई है शुरुआती जांच में मामला किसी जहरीले जीव या कोड़े के काटने से जुड़ प्रतीत हो रहा है।